विचार बिन्दु

हम यहाँ किसी विशेष कारण से हैं। इसीलिए अपने भूत का कैदी बनना छोड़िये। अपने भविष्य के निर्माता बनिए। –रोबिन शर्मा

आर्थिक समीक्षा में माइनिंग सेक्टर ने बनाई विशिष्ट पहचान

माइनिंग सेक्टर आज उभरता हुआ सेक्टर है। निवेश, रोजगार और राजस्व की दृष्टि से खनिज संपदा का महत्व बढ़ता जा रहा है। विपरीत भौगोलिक परिस्थितियां आज राजस्थान के लिए वरदान बन गई है। राजस्थान की धरा की गर्भ में बेशकीमती खनिजों का भण्डार समाया है तो पेट्रोलियम उत्पादों–कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस भी आज राजस्थान की धरा उगल रही है। यही कारण है कि बाड़मेर के पचपदरा में रिफाइनरी बनकर लगभग तैयार है तो दूसरी और स्ट्रेटेजिक और क्रिटिकल मिनरलों में भी राजस्थान दुनिया के नक्शें पर आज प्रमुखता से उभरा है। माइनिंग सेक्टर में राजस्थान देश दुनिया का प्रमुख केन्द्र बन कर उभर रहा है। प्रदेश में कई महत्वपूर्ण खनिज तो ऐसे है जिसमें राजस्थान का लगभग एकाधिकार है। राज्य बजट के साथ प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा के तथ्यों पर एक नजर दौड़ाई जाए तो पोटाश, सिल्वर, जिप्सम, सीसा–जस्ता, वोलास्टोनाइट, आदि मे ंतो 94 प्रतिशत से 88 प्रतिशत तक की भागीदारी राजस्थान की है। डायमेंशनल मिनरल्स में भी राजस्थान अपना विशिष्ठ स्थान रखता है और यही कोई 40 प्रकार के डायमेंशनल स्टोन राजस्थान में मिल रहे हैं।

वैसे तो राजस्थान में 82 प्रकार के मिनरल के संकेत मिलते हैं वहीं 57 मिनरलों को राजस्थान में प्रमुखता से खोज और खनन का कार्य चल रहा है। अब राजस्थान में रेयर अर्थ एलिमेंट आरईई के संकेत मिलने के साथ राजस्थान तेजी से दुनिया के नक्शें पर उभरा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने माइनिंग विभाग की बागड़ोर स्वयं संभाल रखी है जिससे साफ हो जाता है कि राजस्थान की सरकार के लिए माइनिंग सेक्टर प्राथमिकता में की श्रेणी में शुमार है। माइनिंग सेक्टर की महती भूमिका को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने खान मंत्रालय की जिम्मेदारी अपने पास रखी और कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में पिछले कुछ समय में माइनिंग सेक्टर ने खनिज खोज से लेकर माइनर एवं मेजर मिनरल ब्लॉकों के ऑक्शन, एमनेस्टी योजना, ड्रोन सर्वे, एकबारीय समाधान योजना, नई और प्रगतिशील खनिज नीति, एम–सेण्ड नीति, माइनिंग सेक्टर में औद्योगिक निवेश और रोजगार के विपुल अवसर सृजित करने के अवसर विकसित कर दिए हैं। इसके साथ ही पारदर्शी व्यवस्था और प्रक्रिया के सरलीकरण की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाये जा रहे है। समय की मांग को देखते हुए ही आरईई और सेरेमिक आधारित एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे है। राजस्थान माइनिंग के प्रमुख सचिव टी. रविकान्त अथक प्रयासों से धरातल पर ठोस परिणाम प्राप्त करने में जुटे हैं। यही कारण है कि राजस्थान आज देश का माइनिंग सेक्टर में प्रमुख प्रदेश बन गया है। निवेश, रोजगार और राजस्व की दृष्टि से राजस्थान तेजी से आगे बढ़ रहा है।

माइनिंग सेक्टर में राजस्थान देश दुनिया का प्रमुख केन्द्र बन कर उभर रहा है। प्रदेश में कई महत्वपूर्ण खनिज तो ऐसे है जिसमें राजस्थान का लगभग एकाधिकार है। राज्य बजट के साथ प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा के तथ्यों पर एक नजर दौड़ाई जाए तो पोटाश, सिल्वर, जिप्सम, सीसा-जस्ता, वोलास्टोनाइट, आदि में तो 94 प्रतिशत से 88 प्रतिशत तक की भागीदारी राजस्थान की है।

राजस्थान में माइनिंग सेक्टर में ईज ऑफ डूइंग की दिशा में कदम बढ़ाये हैं और सभी प्रकार की आवश्यक अनुमतियां प्राप्त कर प्री एम्बेडेड ब्लॉकों के आक्शन की दिशा में कदम बढ़ाये है तो दूसरी और आटिफिशियल इंटेलीजेंस मशीन लर्निंग की दिशा में कदम बढ़ाये हैं। माइनिंग सेक्टर के महत्व को इसी समझा जा सकता है कि आज डोनाल्ड ट्रम्प खनिजों के लिए दुनिया की देशों को हड़पने के प्रयास और दादागिरी परउतर आया है। चीन का वर्चस्व तोड़ना भी दुनिया के देशों के सामने बड़ी चुनौती है। आज दुनिया के देशों की माइनिग सेक्टर पर अधिक नजर है। खासतौर से अमेरिका तो खनिज बहुल क्षेत्रों में आंखें गड़ाये ही बैठा है वह चाहे यूक्रेन हो, कनाड़ा हो या ग्रीन लैण्ड। तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी है कि रुस यह चाहता है कि अमेरिका और यूक्रेन के बीच खनिज को लेकर कोई समझौता ना हो और इसके लिए वह अपने खनिज क्षेत्रों को लेकर अमेरिका या यों कहें कि ट्रम्प से समझौता तक करने का तैयार है। अमेरिका की कनाड़ा, ग्रीन लैण्ड आदि को लेकर भी तनाव का प्रमुख कारण खनिज संपदा ही है। दूसरी और चीन आज खनिज संपदा के चलते ही समूचे विश्व बाजार पर लगभग एकाधिकार की स्थिति में हैं। दरअसल जिस तरह से दुनिया में नए नए गजेट्स आने लगे हैं, इलेक्ट्रिक वाहन, कार्बन उत्सर्जन के स्तर को कम करने और पर्यावरण को प्रभावित करने वाले उत्पादों के कम उपयोग पर जोर दिया जाने लगा है, उसके कारण खनिज संपदा संपन्न देशों का महत्व और अधिक बढता जा रहा है। चीन के लगभग एकाधिकार के कारण दुनिया के देश त्रस्त भी है। हमारे देश और राजस्थान में भी प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा है।

भारत सरकार ने क्रिटिकल मिनरल ब्लाकों के ऑक्शन की नीलामी अपने हाथ में ली है तो मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्य में निजी प्लेयर्स की भी भागीदारी तय की जा रही है। समूचे देश में पिछले एक दशक में मिनरल एक्सप्लोरेशन के कार्य में तेजी आई है। हमारे देश में सतत खनन विकास पर जोर दिया जाने लगा है और 2016–17 से मेजर हो या माइनर मिनरल सभी माइंस नीलाम करना अनिवार्य कर दिया गया है। बदली परिस्थितियों में यह भी साफ हो जाना चाहिए कि सरकारों की ईच्छा शक्ति पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसका ताजातरीन उदाहरण राजस्थान सरकार और राजस्थान का खान एवं भूविज्ञान मंत्रालय है। देश–दुनिया में माइनिंग सेक्टर को नई पहचान देने के कारगर प्रयास राजस्थान में भजन लाल शर्मा सरकार ने कर के दिखाया है। राजस्थान की उपलब्धि को केन्द्र सरकार द्वारा भी सराहा गया और इसी 20 जनवरी, 25 को ओडिशा के कोणार्क में आयोजित नेशनल मांइस मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में वर्ष 2023–24 में देश में सर्वाधिक मेजर मिनरल ब्लॉक के ऑक्शन करने पर राजस्थान को प्रथम पुरस्कार देकर राजस्थान के प्रमुख सचिव माइंस टी. रविकान्त को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है।

राजस्थान खनिजों की दृष्टि से समृद्ध प्रदेश हैं। राज्य सरकार ने एक बात साफ समझी है कि बेशकीमती खनिजों के अवैध खनन पर अंकुश लगाने का सबसे कारगर तरीका खनिज क्षेत्रों के ब्लॉक या प्लॉट तैयार कर इन्हें पारदर्शी तरीके से ई पोर्टल के माध्यम से नीलाम किया जाए। इससे बहुत हद तक बेशकीमती खनिजों के अवैध खनन को रोका जा सकता है। अरावली और पर्यावरण संरक्षण जहां सस्टेनेबल माइनिंग के लिए जरुरी हो जाता है वहीं अवैध खनन पर कारगर रोक से समस्या का समाधान हो सकता है। राज्य सरकार को एक साथ कई मोर्चों पर काम करना होगा जिसमें खासतौर से अरावली सरंक्षण, पर्यावरण को बनाए रखना, अवैध खनन पर रोक रिवर सेंड के विकल्प के रुप में एम सेंड को प्रोत्साहित करते हुए आमजन को प्रेरित करने जैसी दिशा में आगे बढ़ना होगा। इसके लिए जीरो लॉस माइनिंग की दिशा में आगे बढने के लिए देश दुनिया में माइनिंग सेक्टर में आने वाले बदलावों को आत्मसात करने में भी कोई संकोच नहीं करना होगा।

–अतिथि सम्पादक,
डॉ.राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
(वरिष्ठ लेखक)

राशिफल गुरूवार 19 फरवरी, 2026

पंडित अनिल शर्मा

फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, द्वितीया तिथि, गुरूवार, विक्रम संवत 2082, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रात्रि 8:52 तक, सिद्ध योग रात्रि 8:42 तक, कौलव करण दिन 3:59 तक, चन्द्रमा आज दिन 3:00 से मीन राशि में संचार करेगा।

गृह स्थिति: सूर्य–कुम्भ, चन्द्रमा–कुम्भ, मंगल–मकर, बुध–कुम्भ, गुरू–मिथुन, शुक्र–कुम्भ, शनि–मीन, राहु–कुम्भ, केतु–सिंह

आज फुलेरा दोज (स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त), श्री रामकृष्ण परमहंस जयन्ती, पंचक, छत्रपति शिवाजी जयन्ती है। आज से रमजान मु.मास 9 आरम्भ होगा और रोजा आरम्भ होंगे।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ सूर्योदय से 8:28 तक, चर 11:17 से 12:41 तक, लाभ–अमृत 12:41 से 3:24 तक, शुभ 4:53 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 7:04, सूर्यास्त 6:17

मेष

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। संभावित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक यात्रा संभव है। दिन के मध्यान्ह पश्चात घर–गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक धन खर्च हो सकता है।

सिंह

परिवार में आपसी सहयोग–समन्वय बना रहेगा। उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। दिन के मध्यान्ह पश्चात अष्टम चन्द्र शुभ नहीं है।

धनु

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। आज परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। दिन के मध्यान्ह पश्चात परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

वृष

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में आ रही परेशानियां दूर होने लगेंगी। नवीन कार्यों में प्रगति होगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कन्या

विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अस्त–व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

मकर

आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

मिथुन

नवीन कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। दिन के मध्यान्ह पश्चात व्यावसायिक सफलता से मनोबल बढ़ेगा।

तुला

व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच–विचार हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में महत्वपूर्ण परामर्श मिल सकता है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ

व्यावसायिक कार्यों के कारण बाहर जाना पड़ सकता है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। घर–परिवार में सुख–शांति बनी रहेगी।

कर्क

अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। व्यक्तिगत परेशानियां अभी यथावत बनी रहेगी। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। दिन के मध्यान्ह पश्चात शुभ–मांगलिक संदेश प्राप्त हो सकते हैं।

वृश्चिक

घर–परिवार में सुख–शांति बनी रहेगी। परिवार में धार्मिक–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन

घर–गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। समय अनर्गल कार्यों में खराब होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

राजस्थान बजट 2026-27 : राजस्थान के समग्र एवं सतत विकास का रोडमैप

शांतिलाल चप्पलोत

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में यह राजस्थान के समग्र एवं सतत विकास का रोडमैप है। राजस्थान का बजट 2026–27 आठ करोड़ प्रदेशवासियों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का औपचारिक घोषणापत्र है। यह बजट प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को राज्य स्तर पर साकार करने की दिशा में ठोस कदम है। कुल 6 लाख 10 हजार 956 करोड़ रुपये के आकार वाला यह बजट वर्ष 2023–24 की तुलना में 41 प्रतिशत बड़ा है।

यह बजट दस सुदृढ़ स्तंभों आधारभूत संरचना का विस्तार, नागरिक सुविधाओं में सुधार, औद्योगिक विकास और निवेश प्रोत्साहन, मानव संसाधन सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा, पर्यटन और सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण, सुशासन एवं डिजिटल परिवर्तन, कृषि और किसान कल्याण, हरित विकास तथा वर्ष 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था पर आधारित है। स्पष्ट है कि सरकार अल्पकालिक राहत से आगे बढ़कर दीर्घकालिक संरचनात्मक परिवर्तन की दिशा में सोच रही है।

आर्थिक दृष्टि से भी संकेत उत्साहजनक हैं। राज्य की सकल घरेलू उत्पाद 21 लाख 52 हजार 100 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है, जो 2023–24 की तुलना में लगभग 41 प्रतिशत अधिक है। प्रति व्यक्ति आय पहली बार 2 लाख 2 हजार 349 रुपये से अधिक होने का अनुमान है, जो 21.15 प्रतिशत की वृद्धि है। स्पष्ट है कि विकास की रफ्तार केवल सरकारी कागजों तक सीमित नहीं, बल्कि नागरिकों की आय में भी परिलक्षित हो रही है। पूंजीगत व्यय के लिए 53 हजार 978 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो दो वर्ष पूर्व की तुलना में दोगुने से अधिक है। यह निवेश सड़कों, जल, बिजली, चिकित्सा और शहरी ढांचे में दीर्घकालिक संपत्ति सृजन का आधार बनेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 32 हजार 526 करोड़ रुपये और ठीन बजट के तहत 33 हजार 476 करोड़ रुपये का प्रावधान यह दर्शाता है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण को समान प्राथमिकता दी जा रही है।

मानव पूंजी पर निवेश इस बजट की केंद्रीय धुरी है। शिक्षा क्षेत्र के लिए 69 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो वर्ष 2023–24 से 35 प्रतिशत अधिक है। 400 स्कूलों को सीएम राइज विद्यालयों के रूप में उन्नत करने की योजना है। उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार से स्पष्ट है कि सरकार गुणवत्ता आधारित सेवाओं की ओर अठासर है। जयपुर के जे.के. लोन अस्पताल में 500 बेड का आईपीडी टावर और आरयूएचएस में 200 बेड का पीडियाट्रिक आईपीडी इसका उदाहरण हैं। युवा शक्ति को अवसर और पारदर्शिता देने की दिशा में राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना का निर्णय महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन टेस्टिंग सेंटरों के माध्यम से भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने का प्रयास सराहनीय है। पांच वर्षों में 4 लाख सरकारी नौकरियों के संकल्प की दिशा में 1 लाख से अधिक नियुक्तियां दी जा चुकी हैं, 1 लाख 54 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है और 1 लाख पदों का भर्ती कैलेंडर घोषित किया गया है। निजी क्षेत्र में 2 लाख से अधिक रोजगार अवसर सृजित होना भी सकारात्मक संकेत है।

कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 76 लाख किसानों के खातों में 10 हजार 900 करोड़ रुपये से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से स्थानांतरित की गई है। यमुना जल को शेखावाटी क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए 32 हजार करोड़ रुपये के कार्य प्रारंभ होंगे और रामजल सेतु लिंक परियोजना में 26 हजार करोड़ रुपये के कार्यादेश जारी हो चुके हैं। जल प्रबंधन की ये परियोजनाएं आने वाले दशकों में प्रदेश की कृषि संरचना को स्थायित्व देंगी।

महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी ठोस पहल की गई है। स्वयं सहायता समूहों की ऋण सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये और लखपति दीदी योजना में ऋण सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये करना महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने वाला कदम है। जिला स्तर पर रूरल महिला बीपीओ स्थापित करने की योजना ठाामीण महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने की सोच को दर्शाती है।

पर्यटन और विरासत संरक्षण के माध्यम से रोजगार सृजन की संभावनाओं को भी बल दिया गया है। जैसलमेर के ख़ुड़ी में अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन और शेखावाटी की 660 से अधिक हवेलियों के पुनरुद्धार के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को आर्थिक अवसर में बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स की मांगों के परीक्षण के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन यह संकेत देता है कि सरकार प्रशासनिक तंत्र को विकास का सहभागी मानती है। आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के राज्य में क्रियान्वयन पर विचार भी इसी संवेदनशील दृष्टिकोण का हिस्सा है।

समग्र रूप से देखा जाए तो राजस्थान बजट 2026–27 विकास, संतुलन और समावेशन का दस्तावेज है। यह बजट केवल व्यय बढ़ाने का नहीं, बल्कि संरचनात्मक निवेश, मानव विकास और दीर्घकालिक आर्थिक मजबूती का खाका प्रस्तुत करता है। अब वास्तविक कसौटी क्रियान्वयन की होगी। यदि वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित रहा, तो यह बजट राजस्थान को आत्मनिर्भर, समृद्ध और समावेशी विकास की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ाने में सक्षम सिद्ध होगा।

–शांतिलाल चप्पलोत,
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष
राजस्थान

भारत में महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य – एक चुनौती

डॉ. मिनाक्षी धारीवाल

भारत में, विशेष रूप से महिलाओं के लिए मानसिक स्वास्थ्य एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है जिसे अक्सर नज़रअंदाज़ किया जाता है। महिलाओं के अधिकारों में प्रगति के बावजूद भी महिलाओं को लैंगिक भेदभाव, सांस्कृतिक अपेक्षाओं, घरेलू जिम्मेदारियों, सीमित शिक्षा और सामाजिक कलंक जैसी कई मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जिससे उनके लिए मदद मांगना मुश्किल हो जाता है और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कई मामले अनुपचारित रह जाते हैं। इसलिए भारत में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी, जिसमे शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुँच और लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों पर अधिक जोर सम्मिलित है।

जीवन के विभिन्न चरणों में महिलाएँ किशोरावस्था, युवावस्था, गर्भावस्था, मातृत्व और वृद्धावस्था आदि में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न चुनौतियों का सामना करती हैं। किशोरावस्था व युवावस्था में शैक्षणिक तनाव और शारीरिक बनावट संबंधी चिंताओं से लेकर गर्भावस्था व मातृत्व के हार्मोनल परिवर्तनों व तनाव एवं वृद्धावस्था में देखभाल संबंधी बोझ तक इनमें मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक जटिल और आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं।

भारत में महिलाओं को प्रभावित करने वाले सबसे आम मानसिक विकारों में अवसाद और चिंता शामिल है। इसके अलावा दुर्व्यवहार, हिंसा या असुरक्षित वातावरण से उत्पन्न आघात, शारीरिक बनावट और सामाजिक तुलना का दबाव, खान–पान संबंधी विकार, हार्मोनल परिवर्तनों जैसे प्रसवपूर्व, प्रसवोत्तर अवसाद, पैरीमैनोपौज़, मैनोपौज संबंधी मनोविकार, घर और कार्यस्थल की दोहरी जिम्मेदारियाँ, आर्थिक निर्भरता, नौकरी की असुरक्षा, पितृसत्तात्मक मानदंड आदि बहुत ही लंबी सूची है।

अध्ययनों से पता चलता है कि भारत में महिलाओं में पुरुषों की तुलना में अवसाद से पीड़ित होने की संभावना दोगुनी होती है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निम्हान्स) के अनुसार अवसाद भारतीय महिलाओं में सबसे आम मानसिक स्वास्थ्य विकारों मे से एक है और इसकी व्यापकता लगभग 40 प्रतिशत है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस बात पर प्रकाश डाला है कि युवा भारतीय महिलाओं में आत्महत्या की दर वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक है। लैंगिक भेदभाव,घरेलू हिंसा, यौन शोषण, भावनात्मक उपेक्षा और शिक्षा की कमी महिलाओं को अवसाद के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है। इन समस्याओं के कारण जो आघात महिलाओं की मानसिक स्थिति को पहुंचता है वह और भी समस्या को भयावह बना देता है।

भारत में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक और चुनौती संस्कृतिक अपेक्षाएँ हैं। भारतीय समाज महिलाओं पर पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं के अनुरूप चलने का बहुत दबाव डालता है। अत्यधिक अपेक्षाओं को पूरा करने में असफलता सामाजिक अलगाव और शर्मिंदगी का कारण बन सकती है, जो मानसिक विकारों में बढ़ावा दे सकती है।

भारत में मानसिक स्वास्थ्य उपचार प्राप्त करने में महिलाओं के लिए सामाजिक कलंक भी एक बड़ी बाधा है। मानसिक बीमारी को अधिकतर व्यक्तिगत विफलता के रूप में देखा जाता है और इन्हें कभी–कभी परिवार व समुदाय द्वारा बहिष्कृत भी कर दिया जाता है। इस कारण महिलाएँ समय पर अपने लिए मदद भी नहीं मांग पाती क्योंकि उनको आलोचना व अस्वीकृति का डर होता है। भारत में महिलाओं के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच एक और चुनौती है। ये सेवाएँ ग्रोमीण क्षेत्रों में कम पहुँचती हैं और बहुत महंगी भी होती हैं। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर न होने के कारण महिलाएँ मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए उपचार करने से भी हिचकती हैं।

इसके अलावा खान–पान संबंधी विकार जैसे एनोरेक्सिया नेर्वोसा, बुलिमिया और बिंज–इटिंग डिसोर्डर आदि युवा महिलाओं के बीच बढ़ती चिंता का विषय है। सोशल मीडिया, विज्ञापन और पतलेपन को महिमामंडित करने वाले संस्कृतिक आदर्श शरीर के प्रति असंतोष और हानिकारक खान–पान संबंधी व्यवहारों को बढ़ावा दे सकते हैं। हमेशा दूसरों से तुलना करना, वजन बढ़ने का डर, खाने को लेकर अपराधबोध, कम आत्मसम्मान और आत्ममूल्य आदि शारीरिक छवि से जुड़ी समस्याएँ हैं जो आज की युवा महिलाओं को बहुत प्रभावित करती है।

महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान प्रसवपूर्व अवसाद के लक्षण दिखाई देते हैं। हार्मोनल बदलाव, शारीरिक परेशानी, रिश्तों मे तनाव व प्रसव का डर आदि ऐसे कारण हैं जो महिलाओ में उदासी, चिड़चिड़ापन, अत्यधिक दबाव व नींद संबंधी विकार के लक्षण दिखने लगते हैं। भारत में लगभग 20 प्रतिशत नई माताओं को प्रसवोत्तर अवसाद प्रभावित करता है, सामाजिक सहयोग की कमी, नींद की कमी और आदर्श माँ बनने का दबाव जैसे कारक भी इस समस्या को बढ़ाते हैं।

मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कलंक और अंधविश्वासों को कम करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए शिक्षा अभियान शामिल हों। लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए, जिससे मानसिक स्वास्थ्य परिणामों में सुधार हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ और सस्ता बनाने की आवश्यकता है विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में।

खान–पान संबंधी व शरीर की छवि से जुड़ी चिंताओं व समस्याओं को दूर करने के लिए मनोशिक्षा, परामर्श, पोषण संबंधी मार्गदर्शन किया जाये तथा समाज में बॉडी शैमिंग जैसे कलंक को दूर कर सकारात्मक वातावरण बनाया जाये। प्रसवपूर्व व प्रसवोत्तर अवसाद की समस्याओं को जल्दी पहचानना व परामर्श, घर मे सभी की सहायता मिले, चिकित्सा देख–भाल प्रदान करना, सामाजिक सहयोग आदि माँ शिशु के बंधन को काफी हद तक बेहतर बना सकता है और उनकी मानसिक स्थिति को भी अच्छा बना सकता है। मातृ व प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं में मानसिक स्वास्थ्य जांच को एकीकृत किया जाना चाहिए, किफ़ायती महिला परामर्श की उपलब्धता बढ़ाई जानी चाहिए तथा सामुदायिक पहल से महिलाओं में साझा अनुभव व अलगाव में कमी लाई जा सकती है जिससे मदद मांगने को कमजोरी नहीं माना जाएगा।

घरेलू हिंसा, यौन शोषण या भावनात्मक उपेक्षा से उत्पन्न आघात से जो महिलाओं की मानसिक स्थिति बदतर हो जाती है उसे अगर हमे दूर करना है तो हमारे समाज को इन्हे सुरक्षित और भेदभाव रहित वातावरण देना होगा तथा महिलाओं को सशक्त बनाना होगा। परिवार और समुदाय मानसिक समस्याओं पर खुल कर बातचीत करे इससे पूर्वागृह कम होंगे, देखभाल की जिम्मेदारियो को साझा किया जाये, घर व समाज के लोग महिलाओं को परामर्श व पेशेवर सहायता प्रदान करने मे मदद करें जिससे उनको भी इस समाज का सदस्य होने के नाते मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति हो।

महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता कोई सीमित मुद्दा नहीं है बल्कि यह एक सार्वजनिक प्राथमिकता है। जीवन के विभिन्न चरणों में आने वाली मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों के प्रति संवेदनशील होकर और उनका निराकरन करने की आवश्यकता है तभी स्थायी परिवर्तन लाया जा सकता है।

-डॉ. मिनाक्षी धारीवाल,
असिस्टेंट प्रो.कानोडिया
महिला महाविद्यालय, जयपुर

राजस्थान विश्वविद्यालय का भूमि घोटाला: विरासत की नीलामी या प्रशासनिक षड्यंत्र?

प्रो. अशोक कुमार

जयपुर की पहचान यहाँ के गुलाबी पत्थरों और ऐतिहासिक स्मारकों से ही नहीं, बल्कि यहाँ के उन शिक्षण संस्थानों से भी है जिन्होंने आधुनिक राजस्थान की नींव रखी। महाराजा और महारानी महाविद्यालय केवल दो कॉलेज नहीं, बल्कि एक जीवित विरासत हैं। लेकिन हाल ही में सामने आए तथ्यों ने राजस्थान विश्वविद्यालय के इतिहास में एक काला अध्याय लिख दिया है। इन कॉलेजों की अरबों रुपये मूल्य की भूमि का स्वामित्व चुपचाप जयपुर विकास प्राधिकरण और नगर निगम को हस्तांतरित कर दिया गया। यह घटना न केवल विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर प्रहार है, बल्कि प्रदेश के शैक्षिणक भविष्य के साथ एक क्रूर मजाक भी है।

दस्तावेजों और आधिकारिक सूचनाओं के अनुसार, महाराजा कॉलेज की 48 बीघा 10 बिस्वा और महारानी कॉलेज की लगभग 30 बीघा (कुल 99 बीघा से अधिक का परिसर) भूमि का मालिकाना हक राजस्व रिकॉर्ड में बदल दिया गया है। अपना खाता पोर्टल के डिजिटल रिकॉर्ड बताते हैं कि यह नामांतरण संख्या 49 और 50 के माध्यम से मई–जून 2025 में ही पूर्ण कर लिया गया था।

आश्चर्य की बात यह है कि जिस विश्वविद्यालय प्रशासन को अपनी एक–एक इंच जमीन की रक्षा करनी चाहिए थी, उसे इस बात की भनक तक नहीं लगी–या फिर शायद भनक लगने दी गई और जानबूझकर चुप्पी साधी गई। डॉ. भूपेंद्र सिंह शेखावत (अध्यक्ष, श्री बिशन सिंह शेखावत शोध एवं शिक्षण संस्थान, जो की राजस्थान विश्वविद्यालय में एक जनसंपर्क अधिकारी के रूप में अपनी प्रशंसनीय सेवाएं इस विश्वविद्यालय को दे चुके हैं, पूरे देश में पहली बार राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए लागू की गई इंश्योरेंस योजना जैसे अनेक अभिनव कार्य इन्हीं की पहल पर प्रारंभ हुऐ,) ने इस पर गंभीर सवाल उठाए थे कि जब यह प्रक्रिया 7 महीने पहले ही पूरी हो चुकी थी, तो कुलपति कार्यालय ने इसे सिंडिकेट से क्यों छुपाया? इस पूरे हस्तांतरण में कानूनी प्रक्रियाओं को ताक पर रख दिया गया है।

भूमि का स्वरूप: राजस्व विभाग ने संभवतः इस भूमि को सिवायचक (राजकीय बंजर भूमि) मानकर हस्तांतरित किया है। जबकि वास्तविकता यह है कि यह भूमि पूर्व जयपुर रियासत द्वारा विशेष रूप से शिक्षा हेतु हस्तांतरित की गई हेरिटेज संपत्ति है।

मौका निरीक्षण का अभाव: किसी भी भूमि के नामांतरण से पूर्व भौतिक सत्यापन अनिवार्य है। इन परिसरों में दशकों से भवन बने हुए हैं, हजारों छात्र पढ़ रहे हैं, फिर राजस्व अधिकारियों ने इसे खाली या हस्तांतरण योग्य कैसे मान लिया?

अधिनियम का उल्लंघन: राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 86(2) स्पष्ट करती है कि यदि कोई नामांतरण गलत तरीके से हुआ है, तो 3 माह के भीतर उसका पुनरावलोकन कर उसे खारिज किया जा सकता है। लेकिन यहाँ प्रशासन ने समय निकलने का इंतजार किया ताकि स्थिति यथावत हो जाए।

विश्वविद्यालय प्रशासन की भूमिका: रहस्यमयी चुप्पी के मायने

किसी भी स्वायत्त विश्वविद्यालय का सर्वोच्च निर्णयकारी अंग उसकी सिंडिकेट होती है। विश्वविद्यालय की संपत्ति का एक हिस्सा भी यदि किसी अन्य संस्था को दिया जाता है, तो सिंडिकेट की अनुमति अनिवार्य है। यहाँ तो पूरे के पूरे कॉलेज की जमीन ही छिन गई।

कुलपति की भूमिका यहाँ संदेह के घेरे में है। यदि कुलपति को इसकी जानकारी थी, जैसा कि व्हाट्सएप संदेशों और चर्चाओं से संकेत मिलता है, तो उन्होंने सिंडिकेट की आपात बैठक क्यों नहीं बुलाई? क्या विश्वविद्यालय प्रशासन पर किसी राजनीतिक या भू–माफिया दबाव का साया था? यह उदासीनता न केवल प्रशासनिक विफलता है, बल्कि विश्वविद्यालय के प्रति विश्वासघात की श्रेणी में आती है। इस भूमि की बाजार दर आज की तारीख में अरबों रुपये में है। लेकिन नुकसान केवल आर्थिक नहीं है:

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के अनुसार, किसी भी संस्थान को ग्रांट या फंड तभी मिलता है जब भूमि उसके नाम पर दर्ज हो। स्वामित्व छिनने के बाद महाराजा और महारानी कॉलेज भविष्य में किसी भी केंद्रीय सहायता से वंचित हो सकते हैं।

विकास कार्यों पर रोक: यदि कल विश्वविद्यालय को नए लैब, डिजिटल लाइब्रेरी या हॉस्टल बनाने हों, तो उसे जेडीए या नगर निगम के सामने हाथ फैलाने होंगे।

निजीकरण का डर: अंदेशा यह भी है कि जेडीए इस प्राइम लोकेशन की जमीन का उपयोग कमर्शियल उद्देश्यों या सार्वजनिक–निजी भागीदारी मॉडल के लिए कर सकता है, जिससे शिक्षा महंगी और दुर्गम हो जाएगी।

जन–आंदोलन की आवश्यकता: अब नहीं तो यह लड़ाई केवल कागजों तक सीमित नहीं रह सकती।

सिंडिकेट की विशेष बैठक: कुलपति को तत्काल प्रभाव से बैठक बुलाकर इस निर्णय के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करना चाहिए और इसे राजभवन भेजना चाहिए।

डिजिटल विरोध: विश्वविद्यालय के हजारों शिक्षकों, कर्मचारियों और पूर्व छात्रों को मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ईमेल के जरिए अपनी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए।

सोशल मीडिया का मोर्चा: आर यू परिसर बचाओ जैसे अभियानों के माध्यम से आम जनमानस को यह बताना होगा कि कैसे उनकी विरासत को चुपचाप बेचा जा रहा है।

निष्कर्ष: अस्मिता का प्रश्न

महाराजा और महारानी कॉलेज राजस्थान की अस्मिता हैं। यदि आज हम इस प्रशासनिक सर्जिकल स्ट्राइक पर मौन रहे, तो कल विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर भी सुरक्षित नहीं रहेगा। यह समय है कि राज्य सरकार अपनी गलती सुधारे और कुलाधिपति (राज्यपाल) महोदय हस्तक्षेप कर इस अवैध नामांतरण को निरस्त करवाएं। शिक्षा के मंदिरों को राजस्व और संपत्ति के खेल से दूर रखना ही एक सभ्य समाज की पहचान है।

–प्रो. अशोक कुमार,
पूर्व कुलपति, कानपुर,
गोरखपुर विश्वविद्यालय, पूर्व
विभागाध्यक्ष राजस्थान
विश्वविद्यालय